>

Title : Need to sanction the estimates submitted by the Government of Rajasthan for National Highway Projects in the State.

**प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर):** राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के अंतर्गत राजस्थान के राजमार्गों की वार्षिक योजना 2007-2008 के 39 कार्यों हेतु 253.84 करोड़ लागत के प्राक्कलन बनाकर केन्द्र सरकार को वांछित स्वीकृति हेतु जुलाई 2007 में प्रस्तुत कर दिए गए थे। परन्तु अभी तक मात्र 77.67 करोड़ रुपए राशि के 15 प्राक्कलनों की ही स्वीकृत केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई है। इसके अलावा अन्य कामों के प्राक्कलन भी बना लिए गए हैं, परन्तु उन्हें पूर्व में प्रेषित प्राक्कलनों की स्वीकृति के अभाव में केन्द्र सरकार को प्रस्तुत नहीं किया गया है। राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्राक्कलनों में स्वीकृति के विलंब के कारण कार्यों में अनावश्यक विलंब होता है तथा निर्धारित राशि का समय पर उपयोग भी नहीं हो पाता। उक्त संदर्भ में राज्य सरकार ने केन्द्रीय मंत्रालय को 11.9.2007 की बैठक में यह सुझाव भी दिया था कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम संपर्क सड़क योजना कार्यों की स्वीकृति के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वही प्रक्रिया पोत एवं सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भी राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों की स्वीकृति हेतु अपना ली जाए तथा मंत्रालय प्राक्कलनों की स्वीकृति के लिए मानदंड निर्धारित कर दे और केन्द्रीय सड़क निधि कार्यों की भांति प्राक्कलनों को स्वीकृति करने का अधिकार राज्य सरकारों को दे दे। इस सुझाव को मानने से समय पर स्वीकृति और निर्णय आदि से राष्ट्रीय राजमार्गों के बेहतर रखरखाव एवं विकास का कार्य गति पकड़ सकता है ।

अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रेषित वार्षिक योजना के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों को वार्षिक योजना 2007-08 के प्राक्कलनों की अविलंब स्वीकृत प्रदान करे तथा राज्य सरकार द्वारा सुझाए गए उपाय को भी दृÂिष्टगत रखकर शीघ्र ही उचित कार्यवाही की जाए।